IJAER/ July-August 2020/Volume-9/Issue-1 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

Covid–19 इन इंडियन इकॉनोमी

दिनेश महादेव ढगे

सहाय्यक प्राध्यापक

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती

सार

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मार्च 2020 (दूसरे सप्ताह) के लंबे खंड में कोरोना (कोविड–19) प्रकरण को एक महामारी घोषित कर दिया था। लाख के अलावा 1 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया (लगभग 170 राष्ट्रय मुख्य भूमि पर) संक्रमण को तुरंत रोकने के लिए किसी भी टीकाकरण के बिना बहुत ही निराशाजनक रूप से सहन कर रही है। संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए सुलभ एक प्रमुख सफल उपकरण के रूप में, राष्ट्र रक्षाहीन रूप से लॉकडाउन का अभ्यास कर रहे हैं। यह निस्संदेह राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को प्रभावित करेगा और लंबे समय में विश्वव्यापी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह ग्रह पर 100 वर्षों की सबसे बड़ी खामोशी लाएगा। इंडियाय एक तेजी से उभरते हुए राष्ट्र के रूप में इस सामान्य विशिष्टता के अविश्वसनीय रूप से गंभीर प्रभाव का सामना करना चाहिए।

मुख्य शब्द: *कोविड–19, भारतीय अर्थव्यवस्था*

परिचय

महामारियाँ शक्तिशाली बीमारी का विशाल दायरा विस्फोट हैं जो पूरी दुनिया में अत्यधिक अंधकार और मृत्यु दर का निर्माण कर सकती हैं और बुनियादी मौद्रिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिर प्रभाव पैदा कर सकती हैं। वास्तविकताएं बताती हैं कि पिछली शताब्दी में व्यापक यात्रा और मिश्रण, शहरीकरण और सामान्य जलवायु के महत्वपूर्ण दुरुपयोग के बाद से महामारी की संभावना बढ़ गई है। ये उदाहरण शायद जारी और बढ़ते रहेंगे। उत्कृष्ट कार्यप्रणाली ने उन विस्फोटों के सुधार को पहचानने और सीमित करने के लिए सोचा है जो महामारी को प्रेरित कर सकते हैं। दिमागीपन और समृद्धि की सीमा को विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों के बावजूद, बुनियादी उद्घाटन और कठिनाइयाँ समग्र रूप से अपरिहार्य स्थिति में मौजूद हैं। आईएचआर को इकट्ठा करने की दिशा में आंदोलन एकतरफा हो गया है, और विभिन्न देशों ने स्थिरता के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को अपर्याप्त माना है।

विभिन्न प्रकरणों, प्रसिद्ध रूप से पश्चिम अफ्रीका इबोला प्लेग (2014) ने बीमारी के पूर्ण रहस्योद्घाटन, मौलिक विचार की उपलब्धता, संपर्कों का अनुसरण, अलग–अलग और नियंत्रण रणनीतियों के साथ–साथ समग्र समन्वय और प्रतिक्रिया की तैयारी के साथ जुड़े हुए फांक को उजागर किया है। ये उद्घाटन संपत्ति में विशेष रूप से स्पष्ट हैं प्रतिबंधित सेटिंग्स और एक निर्विवाद समग्र व्यापक के बीच में क्या हो सकता है के लिए उन्मत्त विचारों के साथ पास की महामारी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। COVID–19 (कोविड बीमारी 2019) पर वर्तमान महामारी फोकस पहले जीका संक्रमण, भ1छ1, गंभीर तीव्र श्वसन विकार (SARS), चिकनगुनिया, मध्य पूर्व श्वसन स्थिति (MERS), और इबोला पर केंद्रित था। काफी देर में पहला मामला 30 जनवरी 2020 को देखा गया था। पिछले कई महीनों से अधिक समय में, सकारात्मक मामले 10,000 हो गए हैं और 400 लोगों की मौत हो गई है। भारत सरकार ने इतने दूर के भविष्य की भयानक स्थिति का पता नहीं लगाया था। अन्य व्यवहार्य उपायों के साथ–साथ देश को सुरक्षित करने के लिए सबसे समयनिष्ठ विकल्प लिया। भारत की केंद्र सरकार

परिस्थिति को दूसरे चरण में ही नियंत्रित करने के लिए मौलिक एकाग्रता के साथ जाँच कर रही है, न कि इसे तीसरे चरण में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए उदाहरण के लिए स्थानीय क्षेत्र में फैला हुआ है। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए घोषित क्रॉस कंट्री लॉकडाउन अब व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। भारत की निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) ने कहा कि ष्भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में तेज गिरावट का सामना करेगी और यह 4.5: तक गिर जाने पर निर्भर है ष्। ष्वे अतिरिक्त रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त वर्ष 2011 के लिए जीडीपी विकास लगभग 2: होगा। ICRA ने भारत के घरेलू बाजार के लिए अपनी चिंता का प्रदर्शन किया है जो चीन की गड़बड़ी की गणना की गई श्रृंखला के कारण उच्च प्रभाव का निरीक्षण करेगा। यह न केवल घरेलू उत्पादन को रोकेगा (चूंकि अपरिष्कृत पदार्थों की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित होती है बल्कि वैश्विक उत्पाद में खेदजनक विकास का भी सामना करना पड़ेगा। वर्तमान ब्टप्क–19 प्रकरण ने विशिष्ट जातीय नींव के व्यक्तियों के खिलाफ सामाजिक अपमान और अनुचित प्रथाओं को उकसाया है, जैसा कि किसी ने भी संक्रमण के संपर्क में देखा था।

आईसीआरए ने भी लॉकडाउन की स्थिति की भेद्यता के बीच निर्माण, संयोजन और प्रशासन उद्यमों के लिए अपनी चिंता प्रदर्शित की है। वे अनुमान लगाते हैं कि मानकीकरण प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को और अधिक विस्तारित अवधि लगेगी। ष्अर्थव्यवस्था का नकारात्मक पैटर्न मार्च 2020 के तीसरे सात दिन से मार्कर देना शुरू कर देगा"। विकास, सराय, लाइव अवसर, यात्रा, यात्रा उद्योग जैसे उद्यम सबसे पहले प्रभावित होंगे क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अनावश्यक है। गंभीर तीव्र श्वसन विकार (SARS) और 2009 महामारी फ्लू । जैसे विश्वव्यापी चिंता के उत्पन्न होने वाली अप्रतिरोध्य बीमारी के अवसरों की बढ़ती संख्या पड़ोस के राज्य संचालित प्रशासनों और वैश्विक स्थानीय क्षेत्र के बीच द्विदिश पत्राचार को बढ़ाने की विशेष आवश्यकता को निर्देशित करती है। इस आवश्यकता को समझते हुए, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क (GOARN) को 2000 में एक विश्वव्यापी सहयोग के रूप में आकार दिया गया था, जो भड़कने वाले अवलोकन और प्रतिक्रिया प्रयासों (8) के लिए विशेष सहायता को मिलाता है, और WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR 2005) में बदलाव किया गया था। टोही सीमा दिशानिर्देशों को ताजा करने और बीमारी के अवसरों का विवरण देने के लिए जिसमें ष्वैश्विक चिंता के सामान्य स्वास्थ्य संकट ष शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति घरेलू रुचि को कम करेगी। बड़े पैमाने पर रोजगार के दुर्भाग्य और अगले कई महीनों के लिए वेतन में लगातार कटौती की स्थिति को बाहर नहीं किया जा सकता है। दुकानदार की जेब में कम नकदी अनावश्यक चीजों का ब्याज देगी और मूल रूप से काम का ही पालन करेगी। चूंकि लॉकडाउन का प्रभाव पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, इसलिए विश्वव्यापी हित एक सत्यापन योग्य सुस्ती की ओर बढ़ जाएगा। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक क्षेत्र अपने आयात को कम कर देंगे, इस प्रकार भारतीय निर्यात घरानों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

पूर्व–कोविड –19 अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था

दुनिया के सभी देशों में ब्याज और आपूर्ति में हस्तक्षेप और बाद में वित्तीय राहत के लिए झटका काफी हद तक सापेक्ष तरीके से काम कर रहा है। अगर किसी भी मामले में भारत की कोई घटना सामने आनी चाहिए, तो यह मुद्दा कैसे अधिक असाधारण और लंबे समय तक पीड़ित हो सकता है, क्योंकि पूर्व–कोविड –19 अवधि में अर्थव्यवस्था जिस एक्सप्रेस में थी, उसके कारण। उस बिंदु पर जब मुख्य कोविड –19 मामले का आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय में प्रतिनिधित्व किया गया था, अर्थव्यवस्था वास्तव में लंबे समय तक कमजोर निष्पादन के बाद बहुत ही बुनियादी स्तर पर कमजोर हो गई थी। कुल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) की उन्नति दर 2015–16 के आसपास शुरू हो रही है। शक्ति के अनुभवों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की प्रगति 2019–20 में घटकर 4.2: हो गई, जो 2002–03 के आसपास शुरू हुआ सबसे कम स्तर है। उद्योग, जो सकल घरेलू उत्पाद के 30: को संबोधित करता है, फ4, 2019–20 में 0.58: तक सिकुड़ गया।

बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर दिखाई दी। किसी भी अर्थव्यवस्था में सुधार का एक बड़ा चालक निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा साहसिक कार्य है। पूर्व–कोविद 19 अवधि में, निजी क्षेत्र की परिकल्पना के स्पष्ट संभावित लाभ घट रहे हैं। 2015–16 और 2019–20 के बीच कुल बकाया परिकल्पना परियोजनाओं में 2.4: की गिरावट आई, हालांकि घोषित किए गए नए प्रयासों में 4: की गिरावट आई, जैसा कि सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) के आंकड़ों से पता चलता है। उपयोग का उपयोग भी गिर रहा था, कई वर्षों से अभूतपूर्व। मेट्रोपॉलिटन यूज डिमांड के हाई रिपीट मार्कर से पता चलता है कि वॉयजर वाहनों की व्यवस्था फरवरी 2020 में अनुबंधित खरीदार ड्यूरेबल्स सुधार के समान है। चारों ओर, मेट्रोपॉलिटन उपयोग में भाप खो गया प्रतीत होता है। सामान्य उपयोग की विशेषताओं के बीच, कमजोर ग्रामीण हित को दर्शाते हुए, क्रूजर सौदेबाजी और खरीदार गैर–टिकाऊ हिस्सा फरवरी 2020 में वापसी में बने रहे। लॉक–डाउन ने उपयोग के हित और निजी प्रयासों की वसूली पर कोई भी शॉट लगाया होगा।

COVID–19 के कारण लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव

प्ब्। रेटिंग कार्यालय द्वारा यह आकलन किया जाता है कि ब्ट्प्ब्–19 आपातकाल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वित्तीय में केवल 2: की दर से विकसित हो सकती है। लॉकडाउन में एक प्रतिकूल राष्ट्र होगा जहां व्यक्तियों को आवश्यकता के वास्तविक परिणामों से काफी अधिक खतरा होता है, यह मानते हुए कि वे काम किए बिना थोड़ी देर चले जाते हैं। भारत में एक विवादास्पद सम्मेलन की घोषणा की गई है जो व्यक्तियों को वह स्थान छोड़ने से रोकता है, लेकिन बुनियादी आपूर्ति, सुपरमार्केट, दवा भंडार, और बैंक विशिष्ट घंटों के लिए सेवा करते रहते हैं जैसा कि सरकारी सार्वजनिक वाहन ने सोचा था कि अतिरिक्त आदेश तक पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण, भारत में तुच्छ चीजों का संयोजन क्षेत्र बंद है, जिससे श्रम शक्ति में कमी आ रही है और नए प्रतिनिधि को सूचीबद्ध करने की कोई संभावना नहीं है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में विवेकाधीन नकदी प्रवाह गिर जाएगा, कुल ब्याज में गिरावट का पालन करें और जैसा कि कुल ब्याज और कुल स्टॉकपाइल अपस्फीति के बीच अपस्फीति छेद इस बात की उपयुक्त संभावनाएं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति में धकेल दिया जा सकता है।

एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, 20.03.2020 को, COVID–19 भड़कने से भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू उपयोग दुर्भाग्य के करीब + 387 मिलियन और + 29.9 बिलियन के बीच खर्च हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और स्पेन में पीड़ित पीड़ितों की संख्या ने अब तक चीन से बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत के प्रस्तावित समूह असुरक्षित होते जा रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को विनाशकारी रूप से प्रभावित करेंगे।

COVID–19 और उसके बाद का लॉकडाउन भारतीय अर्थव्यवस्था को दो तरह से प्रभावित कर सकता है, एक दूर से, इसमें शामिल हैरू अधिक नाजुक विश्वव्यापी हित, स्टोर नेटवर्क रुकावट, कम आइटम लागत, और जोखिम–बंद और वैश्विक मौद्रिक झटके। दूसरा इसके अंदर घरेलू चौनलों के माध्यम से है, जिसमें शामिल हैंरू कम वैकल्पिक खर्च, औद्योगिक सुविधा बंद, और यात्रा सीमाएं। यह स्पष्ट है कि COVID–19 महामारी के कारण होने वाले एक साथ काम करने वाले झटके का एक आकर्षक प्रदर्शन होगा। विश्वव्यापी विनिमय चीन के बंद होने और निलंबन के कारण आने वाले आपूर्ति–पक्ष के झटके से प्रमुख घबराहट जुड़ी हुई है, साथ ही भारत को वित्तीय झटके का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि महामारी को सामान्य स्वास्थ्य संकट के रूप में घोषित किया गया है और तीसरा झटका तेल की लागत से उभरेगा क्योंकि विश्वव्यापी हित में गिरावट, हम पर्यवेक्षक उनकी लागतों में गिरावट कर सकते हैं।

भारत में मौद्रिक व्यापार क्षेत्र बेहद अप्रत्याशित हैं, और इन झटकों का जवाब अनंतता में दे रहे हैं और परिस्थिति पहले की तरह एक संदिग्ध अवधि के लिए जारी रहेगी। इन झटकों को देखते हुए, लॉकडाउन से भारत को लगभग 120 बिलियन अमरीकी डालर का नुकसान होगा। संयोजन और प्रशासन क्षेत्र एक अप्रत्याशित विराम पर पहुंच गया है और घरेलू स्टॉक चेन पर घुसपैठ कर रहा है। जैसे–जैसे संगठनों की आय कम होती जाएगी, आधिकारिक कार्यकर्ता और प्रतिदिन कमाने वाले आग की कतार में होंगे। इसके प्रभाव में क्षेत्र के अनुसार

उतार–चढ़ाव होगा, फिर भी प्रशासन विशेष रूप से कठिन होगा और आधुनिक और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में लंबे समय तक ब्याज और सीमा के नुकसान का खतरा है, यह मानते हुए कि आपात स्थिति समाप्त हो गई है। 20 फरवरी, 2020 को क्रेडिट स्कोर इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने व्यक्त किया कि भारत की अर्थव्यवस्था असाधारण संकट में होगी यदि महामारी एक व्यापक खिंचाव के लिए आगे बढ़ती है। जैसा कि पारिवारिक क्षेत्र को अंदर रहने के लिए संपर्क किया गया है, कुल उपयोग में गिरावट आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में वेतन की गोल चक्कर प्रगति को झटका लगेगा।

उड़ानें बंद होने के साथ, वीजा बंद हो गया, परिवहन निलंबित हो गया, शून्य आवास, शॉपिंग सेंटर, मल्टीप्लेक्स और भोजनालय बंद हो गए, भारत में संगठन असमान रूप से निचले स्तर पर हैं। कमजोरियों, सवालों और महामारी के कारण के बारे में कम स्पष्टता के कारण, कुक्कुट वस्तुओं के लिए रुचि प्रभावशाली रूप से कम हो गई है। वास्तविक सीमाओं ने सहायता क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। व्यापार की मात्रा में गिरावट और संपत्ति का अपूर्ण उपयोग संगठनों के लिए दुर्भाग्य लाएगा। यह दर्शाए गए क्रेडिट को नुकसान पहुंचा सकता है। निम्नलिखित वित्तीय के दौरान सकल घरेलू उत्पाद विकास भारत में महामारी के प्रभाव में 3.5: तक गिरने पर निर्भर है और 21 दिनों के लिए बाद में लॉकडाउन भारत के मौद्रिक दृष्टिकोण के लिए एक भौतिक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद होने वाले अमित्र प्रभाव कच्चे पेट्रोलियम की लागत में तेज गिरावट, और अपेक्षित धन संबंधी और वित्तीय वृद्धि से बढ़ने की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा इंगित बेरोजगारी दर अप्रैल 2020 के मुख्य सात दिनों में बेरोजगारी दर में 23.8: की वृद्धि करती है, कार्य सहयोग दर 39: तक गिर गई और व्यापार दर 30:8 थी। ब्टप्क–19 को कम करने के लिए किए गए लॉकडाउन ने प्रांतीय पदों के तहत मजदूरों को धीमा कर दिया है, षडयंत्र सुनिश्चित करते हैं, दिहाड़ी मजदूरों को कम से कम शपथ दिलाते हैं। जैसा कि महत्वपूर्ण संगठनों को स्थगित करने की आवश्यकता है, इसने मुख्य रूप से प्रांतीय और महानगरीय क्षेत्रों में आकस्मिक अर्थव्यवस्था में रोजाना कमाने वालों, आधिकारिक श्रमिकों और स्वतंत्र रूप से नियोजित विशेषज्ञों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उन्हें देश की उच्च बेरोजगारी दर के बीच व्यवसायों से बाहर कर दिया गया है। मनरेगा 266 मिलियन विशेषज्ञों का उपयोग करता है, जिनमें से 128.1 मिलियन गतिशील हैं, जैसा कि साइट द्वारा इंगित किया गया है, निरंतर मौद्रिक वर्ष में योजना के तहत 54 मिलियन परिवारों के 77.5 मिलियन लोगों का उपयोग किया गया है। बढ़ती बेरोजगारी दर का अर्थ है वेतन का कम फैलाव और कम क्रय शक्ति जो नकारात्मक निवेश निधि को प्रेरित करेगी और उपयोग के उपयोग में गिरावट आएगी।

बाद में उभरती हुई ब्याज की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक खींचे गए प्रभाव के साथ मंदी की स्थिति पैदा कर सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए, यह तर्क दिया जा सकता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को मौद्रिक आंदोलन के कुल लॉकडाउन के समान ही खोलना चाहिए था। फिर भी, यदि हम स्वीडिश मॉडल का मूल्यांकन करते हैं, तो भारत की तरह बिल्कुल नहीं, उन्होंने सीमाओं को बाध्य नहीं किया बल्कि उन्होंने लोगों को आत्म–अनुशासन के लिए प्रोत्साहित किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में राज्य रोग संचरण विशेषज्ञ एंडर्स टेगनेल ने स्वीडन से संबंधित निवासियों को मौद्रिक अभ्यास के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया, जब तक कि वे विशेष रूप से कमजोर न हों, भले ही उनके रिश्तेदार दागी हों। 4 मई, 2020 तक स्वीडन में 10.3 मिलियन की कुल आबादी में से 22721 लोग दागी हो गए हैं, जबकि भारत की तुलना में, स्वीडन में कुल 1380 मिलियन 42836 आबादी में से, 2769 लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में 1389 लोगों की जान गई10,11। दो परिस्थितियों में भारत के लॉकडाउन के फैसले का बचाव किया जाता है, शायद उसे जान बचाने का भरोसा है, जो अर्थव्यवस्था को बचाएगा।

क्रियाविधि

वर्तमान शोध पत्र, साइट, पेपर लेख, पत्रिकाएं, सरकारी रिपोर्ट, डायरी आदि जैसे वर्तमान मुद्दों पर जानकारी एकत्र करके माध्यमिक डेटा का उपयोग कर रहा है। परीक्षा महत्वपूर्ण। सर्वेक्षण प्रणाली लिखना वैकल्पिक सूचना आधार

ऑडिट करने के लिए एक प्रदर्शित उपकरण है। वे भविष्य की परीक्षा के लिए मजबूत औचित्य प्रदान करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। वैसे भी एक लेखन समीक्षा को निर्देशित करना और तकनीकी कारणों से इसका उपयोग करना दोनों ही लगातार परीक्षण कर रहे हैं। जैसा भी हो, इस समीक्षा में हमने वास्तव में इसी तरह की परीक्षा को निर्देशित करने के विरोध में दिमागी दबदबा सटीकता पर विस्तार करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल किया था। यह विषय की बेहतर समझ और सिद्धांत की नींव के लिए स्पष्ट दृष्टि देता है।

परिकल्पना

1. नल (H1): भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID–19 की घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है।
2. वैकल्पिक (H1)रू भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID–19 की घटनाओं के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

COVID–19 – एक आर्थिक झटका

ब्व्टप्क–19 महामारी के प्रकोप के साथ आगे बढ़ने से विश्व अर्थव्यवस्था पर काले बादल छा गए हैं। दुनिया भर में मंदी सबसे भयानक रूप में लौट सकती है। इससे गड़बड़ी स्टॉक नेटवर्क को बोर्ड मिल जाएगा जिससे चीन जैसा देश बुरी तरह प्रभावित होगा। लगभग पूरी दुनिया की लॉकडाउन स्थिति निश्चित रूप से ब्याज को कम करेगी जो दुनिया की वित्तीय स्थिति को अनियमित करेगी। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा जैसे अमेरिकी डॉलर भी प्रभावित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक पिछले वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में लगभग एक अवरोही पैटर्न दिखा रही थी। चालू मौद्रिक वर्ष 2019–20 की दूसरी और तीसरी तिमाही में 8ः से 4.5ः। विश्व महामारी आउट ब्रेक ने भारत पर बेहद प्रतिकूल समय में हमला किया है। विश्व आर्थिक आउटलुक, ष्अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्तमान में वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत की विकासशील प्रगति को 4.8ः तक कम कर दिया है और इसे वित्त वर्ष 2020 के लिए 1.2ः अतिरिक्त कर दिया हैष्। यह बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स COVID–19 के भड़कने से पहले ही आई थीं। यह सामान्य है कि बाद में कोरोनाय स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में विमुद्रीकरण और जीएसटी निष्पादन (व्यापक रूप से ढांचे को अद्यतन करने के लिए एक कार्य) का सामना किया था। हालाँकि अर्थव्यवस्था इस परिवर्तन के प्रभाव को निगलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैय किसी भी मामले में, अराजक क्षेत्रों को वास्तव में काफी दूर जाने की जरूरत है। इसने कुछ बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। एक जोड़े के लिए एनपीए ने एक ऊर्ध्वाधर पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि वे बीमार व्यापारिक घरानों को संदिग्ध ऋण प्रथाओं से जुड़े थे। भारत विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में अपनी गुणवत्ता का विस्तार करने के लिए कई योजनाओं और योजनाओं के साथ सामने आया, हालांकि अंत में, उनकी धारणा के साथ पर्याप्त विपरीतता नहीं मिली। श्मेक इन इंडियाश ऐसे अभियान के उदाहरणों में से एक है जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों के उत्पाद की मदद करना था।

COVID–19 का प्रभाव

ब्व्टप्क–19 के विश्वव्यापी प्रभाव ने प्रभावी रूप से अपने विशाल प्रभाव को उजागर करना शुरू कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतीक। मौद्रिक क्षेत्र में छाप मिलने की जल्दी है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले हर अगले दिन एक अछूते निचले स्तर पर पहुंच रहा है। अवरोही रुपये की मुक्त प्रगति भारतीय संघ के लिए अमरीकी डालर में अपने योगदान का निपटान करने के लिए एक असाधारण परिस्थिति ले जा रही है। आंतरिक मोर्चे पर, भारत अब लगभग हर क्षेत्र में कम अनुरोधों से जूझ रहा है, उदाहरण के लिए निर्माण, उत्पादन, निर्माण, सेवाएं, रसद, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य, और इसके बाद लॉकडाउन और महामारी को रोकने के अन्य उपायों ने भी घेर लिया है। ब्याज, विशेष रूप से मर्चेंडाइजध्प्रशासन के लिए। तेल की कीमतों में नई गिरावट से कुछ मदद मिली है, लेकिन यह स्थिति के भयानक प्रभाव को कम करने की स्थिति में नहीं है। भारत ने 22 मार्च को एक स्वयंभू श्जांता समय सीमाश की घोषणा की, जिसे देश के निवासियों द्वारा अत्यधिक माना जाता था। वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (30) ने लॉकडाउन की घोषणा की है और विभिन्न उपायों के साथ इसे

वास्तव में लागू किया है, इसका उद्योगों पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। आकस्मिक क्षेत्र के उद्योग और मजदूर वास्तव में व्यापक रूप से प्रभावित होंगे। लॉकडाउन किसी न किसी रूप में संक्रमण के प्रसार की गति को रोक रहा है (यदि इसके विपरीत और अन्य देशों में) लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद इसके पलटाव की उम्मीद को बाहर नहीं किया जा सकता है। श्री विवियन बालकृष्णन, सिंगापुर के माननीय विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा है कि ब्व्टप्क–19 ष्प्रत्येक देश की चिकित्सा देखभाल की प्रकृति, प्रशासन के मानदंड और सामाजिक पूंजी का विश्लेषण है। इस घटना में कि इनमें से कोई भी पर्वत शक्तिहीन है, वह इस प्लेग से खुला और निर्दयता से खुला रहेगा।ष्

व्यापक आर्थिक नीति

इस अशांति के समय में, उद्यमों और व्यक्तियों की राय को प्रेरित करने की मांग को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। एफआरबीएम द्वारा निर्धारित उद्देश्य (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 – मौद्रिक अनुशासन को व्यवस्थित करने के लिए भारत का अधिनियम, भारत की वित्तीय कमी को कम करना, व्यापक आर्थिक प्रशासन पर काम करना और एक उचित खर्च योजना की ओर बढ़ते हुए सार्वजनिक संपत्ति का सामान्य प्रशासन और सुदृढ़ करना मौद्रिक विवेक) को एक या दूसरे को कुछ समय के लिए स्थगित या स्वीकार करने की आवश्यकता है जब तक कि परिस्थिति एकजुट न हो और हमेशा की तरह व्यवसाय में वापस आ जाए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) – राष्ट्र के राष्ट्रीय बैंक ने मौद्रिक दर्द के इस मौसम में मदद करने के लिए सुधार करना शुरू कर दिया है। बैंक ने लंबी दौड़ वाली रेपो गतिविधि (एलटीआरओ) दर में ढील दी है और भारतीय रुपये की मदद के लिए अगले आधे साल के लिए 2 अरब डॉलर की पेशकश की है। साथ ही देश के लोगों के काम के रूप में उद्यमों के अन्य क्षेत्रों की मदद के लिए प्रामाणिक आर्थिक और सामाजिक पैकेज भी घोषित किया है। हालाँकि, त्ठप् और भारत सरकार ने अलग–अलग सुधार किए हैं, वैसे भी यह ज्ञात नहीं है कि ये पर्याप्त हैं या नहीं। कोविड के प्रभाव का आकलन किया जा सकता हैय ठीक है, जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सब कुछ भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह आने वाली कठिनाइयों पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। सरकार को मौद्रिक मोर्चे पर सौदेबाजी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगीय इसे व्यवस्थित करें और सबसे खतरनाक प्रामाणिक उद्घाटन से प्रेरित करें। वित्तीय जरूरतों के साथ–साथ मैत्रीपूर्ण और राजनीतिक योजना में संतुलन की गारंटी देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत अभी पिछले दो वित्त वर्ष में अपनी विकास धारणाओं को इकट्ठा करने में चूक कर रहा है। जीएसटी का वर्गीकरण भी मानक के अनुरूप नहीं है। ब्व्टप्क–19 की स्थिति देश की आर्थिक ताकत को और भी ज्यादा खराब कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस के कारण भारत को उसके एक्सचेंज पर 348 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। स्थानीय और दुनिया भर में लॉकडाउन के समय आकस्मिक रूप से यह आंकड़ा और अधिक बढ़ जाएगा। इसके बाद, शून्य परिकल्पना को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है कि ब्व्टप्क–19 की घटना और भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन के बीच एक बड़ा संबंध है। यह स्वाभाविक है कि इस समय रणनीति, परिवहन, कार्गो और कई अन्य व्यवस्थाओं की लागत बढ़ जाएगी। सरकार इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वैसे भी विशिष्ट प्रभाव केवल ताज की अवधि समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा।

संदर्भ

1ण् अचोनू सी, लापोर्टे ए, गार्डम एमए 2005। ष्एक शिक्षण अस्पताल में एक श्वसन वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने का वित्तीय प्रभावरू सार्स से सीखे गए सबक।ष कैनेडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ 96 (1)रू 52–54।

2ण् बैरेट आर, ब्राउन पीजे 2008। ष्इन्फ्लुएंजा के समय में कलंकरू महामारी की आपात स्थितियों के लिए सामाजिक और संस्थागत प्रतिक्रियाएं।ष संक्रामक रोगों के जर्नल 197 (सप्ल 1)रू एस34–एस37।

3ण चौन ईएच, ब्रेवर टीएफ, मैडॉफ एलसी, पोलाक एम पी, सोनरिकर ए एल, और अन्य। 2010. ष्उभरती संक्रामक बीमारी का पता लगाने के लिए वैश्विक क्षमता।ष संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही 107 (50)रू 21701ृ6।

4ण फिशर जेई, काट्ज आर। 2013। ष्2014 के लिए आगे बढ़नारू वैश्विक आईएचआर (2005) कार्यान्वयन।ष जैव सुरक्षा और जैव आतंकवादरू जैव रक्षा रणनीति, अभ्यास, और विज्ञान 11 (2)रू153–56।

5ण जेफरसन टी, जोन्स एम, दोशी पी, स्पेंसर ई ए, ओनाकपोया आई, और अन्य। 2014। ष्वयस्कों और बच्चों में इन्फ्लुएंजा के लिए ओसेल्टामिविररू नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट की व्यवस्थित समीक्षा और नियामक टिप्पणियों का सारांश।ष ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 348 (अप्रैल)रू जी2545।

6ण मून एस, श्रीधर डी, पाटे एम ए, झा जे के, क्लिंटन सी, और अन्य। 2015. ष्क्या इबोला खेल को बदल देगा? अगली महामारी से पहले दस आवश्यक सुधार। इबोला के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया पर हार्वर्ड–एलएसएचटीएम स्वतंत्र पैनल की रिपोर्ट।ष द लैंसेट 386 (10009)रू 2204ृ21।

7ण पथमनाथन ५, ओश्कॉनर के ए, एडम्स एम एल, राव सी वाई, किल्मारक्स पी एच, और अन्य। 2014। ष्इबोला संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण आवश्यकताओं का तेजी से आकलन– छह जिले, सिएरा लियोन, अक्टूबर 2015।ष रुग्णता और मृत्यु दर साप्ताहिक रिपोर्ट (डब्ॅत) 63 (49)रू 1172–74।

8ण स्मोलिंस्की एम एस, हैम्बर्ग एम। ए, लेडरबर्ग जे। एड। 2003. माइक्रोबियल थ्रेट्स टू हेल्थरू इमर्जेंस, डिटेक्शन एंड रिस्पांस। वाशिंगटन, डीसीरू राष्ट्रीय अकादमियों प्रेस।

9ण डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन)। 2014. ष्आईएचआर कोर क्षमता कार्यान्वयन पर राज्यों की पार्टियों का सारांश 2013 रिपोट: